CC MM YY KK

RNI. No. MAHHIN-2014/55445 Postal Reg.No. NPCity/437/2023-2025 www.kendriyamanavadhikar.com

केन्द्रीय सम्माननीय जीवन समान अधिकार दैनिक

मानवाधिकार

| नागपुर. शुक्रवार, 8 अगस्त 2025 | वर्ष - 13 | अंक - 163 | पृष्ठ - 4 | मुल्य - 2 रु. | संपादक : मिलिंद दहिवले

दैनिक केन्द्रीय मानवाधिकार
हिन्दी समाचारपत्र के लिए चाहिए
पत्रकार, क्राइम रिपोर्टर, फोटोग्राफर, काउंसलर, रिसेप्शनिस्ट, मार्केटिंग विभाग इंचार्ज, न्यूज एंकर, वीडियो एडिटर, टेलीकॉलर, इवेन्ट मैनेजर
M/F उमेदवार शीघ्र संपर्क करे
- मुख्य कार्यालय -
प्लॉट नं. 386, चंदन नगर, नागपुर-440 024
संपर्क - 9552011005

न्यूज गैलरी

महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्यमिता और नवाचार नीति 2025 की घोषणा

मुंबई – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और नवाचार-संचालित अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण के अनुरूप, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में नए उद्यमियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से "महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्यमिता और नवाचार नीति 2025" को मंजूरी दी गई है और इस नीति के आधिकारिक कार्यान्वयन की घोषणा की गई है, कौशल, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने बताया। लोढ़ा ने कहा कि यह नीति कौशल, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग द्वारा तैयार की गई है और इसे महाराष्ट्र राज्य नवाचार सोसाइटी के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। इस नीति का उद्देश्य महाराष्ट्र को भारत में सबसे गतिशील और दूरदर्शी स्टार्टअप केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस नीति में अगले पाँच वर्षों के लिए एक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण है और इसका लक्ष्य 1.25 लाख उद्यमियों को तैयार करना और 50,000 स्टार्टअप को मान्यता देना है। इसका उद्देश्य समावेशिता, नवाचार और आर्थिक लचीलेपन पर ज़ोर देते हुए एक वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। इसमें शहरी, ग्रामीण, महिला और युवा उद्यमियों सहित सभी क्षेत्रों में उभरती प्रौद्योगिकियों और वंचित समुदायों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस नीति का एक महत्वपूर्ण घटक "मुख्यमंत्री उद्यमिता एवं नवाचार कोष" है। इस योजना के अंतर्गत 5 लाख उम्मीदवारों का पंजीकरण किया जाएगा, जिनमें से 1 लाख उम्मीदवारों का चयन मूल्यांकन परीक्षाओं, प्रतियोगिताओं और हैकाथॉन के माध्यम से किया जाएगा। अंतिम चरण का उद्देश्य 25,000 चयनित उम्मीदवारों को तकनीकी सहायता, वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करके सफल उद्यमी/नवप्रवर्तक तैयार करना है। चयनित उम्मीदवारों को वित्तीय संस्थानों के साथ साझेदारी में 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। पाँच वर्षों की अवधि के लिए 500 करोड़ रुपये का एक कोष बनाया जाएगा। इस कोष का प्रबंधन वित्तीय विशेषज्ञों की देखरेख में किया जाएगा। बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने के लिए, सरकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, पॉलिटेक्निक और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में माइक्रो-इनक्यूबेटर स्थापित करेगी, साथ ही प्रत्येक क्षेत्र में समर्पित क्षेत्रीय नवाचार और उद्यमिता केंद्र भी स्थापित करेगी। ये केंद्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीपटेक, फिनटेक, मेडटेक, साइबर सुरक्षा और स्थिरता जैसे उच्च-संभावना वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। राज्य सरकार 300 एकड़ में एक "महाराष्ट्र इनोवेशन सिटी" स्थापित करेगी, जिसे स्टार्टअप्स, कॉर्पोरेट्स, शैक्षणिक संस्थानों और सरकार के लिए एक विश्वस्तरीय अनुसंधान और नवाचार केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।

बिहार मतदाता सूची में दावे और कार्रवाई प्रस्तुत करने की अपील

मुंबई – चुनाव आयोग ने एक बार फिर जनता के साथ-साथ राजनीतिक दलों से यह सुनिश्चित करने की अपील की है कि बिहार की अंतिम मतदाता सूची में कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं और कोई भी अपात्र मतदाता शामिल न हो। एक अगस्त को जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में त्रुटियों को ठीक करने के लिए दावे और आपत्तियां पांच अगस्त 2025 को दोपहर तीन बजे तक प्रस्तुत की जा सकेंगी। हालांकि, अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने कोई दावा या आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। राजनीतिक दलों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय दलों और राज्य दलों से कुल 1,60,813 बीएलए फॉर्म प्राप्त हुए हैं और अभी

तक एक भी मामले का निपटारा नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त, पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने और अपात्रों के नाम हटाने के लिए प्रत्यक्ष मतदाताओं से 2,864 आवेदन प्राप्त हुए हैं, तथा 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके नए मतदाताओं से फॉर्म-6 सहित 14,914 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से किसी भी आवेदन का अभी तक निपटारा नहीं किया गया है। नियमों के अनुसार, सभी दावों का निपटारा संबंधित ईआरओ/एईआरओ द्वारा सात दिनों के बाद किया जाएगा। साथ ही, 1 अगस्त को प्रकाशित मसौदा सूची के बाद किसी भी नाम को सत्यापन और संबंधित व्यक्ति को उचित अवसर दिए जाने के बाद ही बाहर किया जा सकता है, भारत निर्वाचन आयोग ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया है।

महाराष्ट्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला

27% ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे सभी नगर निकाय चुनाव

नई दिल्ली – महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस फैसले के तहत महाराष्ट्र में अब सभी नगर निकाय चुनाव 27% ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे। मुंबई और ठाणे समेत महाराष्ट्र की सभी महानगरपालिकाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव का रास्ता अब साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने अहम फैसले में कहा है कि इन चुनावों में 27% ओबीसी आरक्षण लागू किया जाएगा और नई प्रभाग रचना (वार्ड बंटवारा) के आधार पर ही चुनाव कराए जाएंगे। पिछले कुछ समय से महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव रुके हुए थे, क्योंकि नई प्रभाग रचना और ओबीसी आरक्षण को लेकर कानूनी विवाद चल रहा था। कुछ याचिकाकर्ताओं ने नई वार्ड रचना को कोर्ट में चुनौती दी थी।

सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ, जिसमें

न्यायमूर्ति सूर्यकांत शामिल थे, ने साफ कहा कि... सभी नगर निकाय चुनावों में 27% ओबीसी आरक्षण लागू रहेगा। चुनाव नई प्रभाग रचना के अनुसार ही कराए जाएंगे। नई वार्ड रचना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं।

अब राज्य सरकार को चुनाव आयोग के जरिए : 4 हफ्तों के भीतर अधिसूचना जारी करनी होगी। 4 महीनों के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यह फैसला मुंबई महानगरपालिका के 227 वार्डों समेत महाराष्ट्र के लिए लागू होगा।

1994 से 2022 तक OBC आरक्षण स्थानीय निकाय चुनावों में लागू था। सुप्रीम कोर्ट ने उसी आधार को दोबारा मान्यता दी है। इससे राज्य के ओबीसी समुदाय को बड़ा राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलेगा।

दारु के नशे में सेना के जवान ने कार से कई लोगों को मारी टक्कर, ग्रामीणों ने पीट-पीटकर किया अधमरा

नागपुर – नशे में धुत सेना के जवान को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। कार से बाहर निकाल कर नशे में धुत सेना के जवान को जमकर पीटा गया। उसके चेहरे में गहरे घाव के निशान पड़ गए। नागपुर जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां ग्रामीण इलाके के रामटेक में नशे में धुत सेना के जवान ने अपनी कार से इलाके में हंगामा खड़ा कर दिया। सेना के जवान ने कार से कई लोगों को टक्कर मार दी। साथ ही कई गाड़ियों को भी टक्कर मारी है। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने कार चालक का पीछा किया और उसकी बुरी तरह पीट कर अधमरा कर दिया।

गुस्साए ग्रामीणों ने उसे इतना पीटा कि कार चालक सेना का जवान का चेहरा पूरी तरह से खूना-खच्चर हो गया। चेहरे पर गहरे घाव के निशान पड़ गए। जिस सेना के जवान को पीट-पीटकर अधमरा किया गया है, वो रामटेक के हमलापुरी इलाके का रहने वाला है। इसका नाम हर्षपाल महादेव वाघमारे है। हर्षपाल भारतीय सेना में जवान है। असम में उसकी तैनाती है। वो चार दिन पहले असम से छुट्टी पर अपने गांव रामटेक आया था। अत्यधिक नशे में होने के कारण, वो ठीक से गाड़ी नहीं चला पा रहा था। वो वाहन से अपना संतुलन खो बैठा, जिससे उसने नागरधन गांव में अपनी कार से हंगामा खड़ा कर दिया।

गनीमत रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। इस बीच भागने के प्रयास में हर्षपाल महादेव वाघमारे की कार एक पेड़ से टकरा गई और पास के एक नाले में गिर गई। गुस्साए नागरिकों ने उसका पीछा किया और जमकर पिटाई कर दी। इस पूरे मामले पर रामटेक पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक रविंद्र मानकर ने कहा कि शराब अधिक पीने की वजह से हर्षपाल सड़क पर बुरी तरह से गाड़ी चला रहा था। इसमें कोई घायल नहीं हुआ, जिस वजह से उसे हिरासत में लेकर छोड़ दिया गया है।

प्राकृतिक रेत की तुलना में कृत्रिम रेत का अधिक उपयोग करें - डॉ. विपिन इटनकर

नागपुर – शहरीकरण, शहरों और महानगरों के विस्तार, औद्योगिक क्षेत्रों के कारण, निर्माण क्षेत्र के लिए आवश्यक सामग्रियों की मांग स्वाभाविक रूप से बढ़ी है। चूँकि रेत पूरी तरह से प्राकृतिक तत्व है, इसलिए इसके अत्यधिक उपयोग ने नदियों और उनके पारिस्थितिक तंत्र के लिए बड़े पैमाने पर खतरा पैदा कर दिया है। एक ओर रेत की बढ़ती मांग और दूसरी ओर

इसकी सीमित प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने कृत्रिम रेत के संबंध में एक रणनीतिक निर्णय लिया है। ज़िला कलेक्टर डॉ. विपिन इटनकर ने सभी से अपील की कि वे प्रकृति और नदियों तक सीमित रेत पर अतिक्रमण करने के बजाय, प्राकृतिक रेत, जो निर्माण को उतनी ही मज़बूती देती है, के लिए पहल करें। वे राजस्व सप्ताह के अवसर पर बचत भवन में कृत्रिम रेत नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आयोजित एक संगोष्ठी में बोल रहे थे। इस अवसर पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनि, वीएनआईटी के सिविल विभागाध्यक्ष प्रो. राहुल रालेगांवकर, खनन उपनिदेशक श्रीराम कडू, जिला खनन अधिकारी डॉ. अतुल डोड, जिले के विभिन्न खदान मालिक और खदान मालिक उपस्थित थे।

नागपुर जिले में कृत्रिम रेत के लिए आवश्यक पत्थर बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। सरकार ने सरकारी निर्णय के अनुसार, जिन क्षेत्रों में उत्खनन के लिए जगह उपलब्ध है, वहाँ कृत्रिम रेत उत्पादक एमसैंड इकाइयाँ स्थापित करने का रणनीतिक निर्णय लिया है और इसे बढ़ावा देने का निर्देश दिया है। इस संबंध में, नागपुर जिले के लिए 50 उद्यमियों को अवसर प्रदान किया गया है। जिला खनन विभाग इन 50 उद्यमियों में से पहले 50 पंजीकृत उद्यमियों का चयन करेगा और उन्हें उचित सहायता प्रदान करेगा, जिला कलेक्टर डॉ. विपिन इटनकर ने कहा। कृत्रिम रेत की आवश्यकता केवल महाराष्ट्र में ही नहीं, बल्कि वैश्विक हो गई है। चूँकि रेत की आवश्यकता दोगुनी हो गई है, इसलिए प्राकृतिक रेत से उस मांग को पूरा करना संभव नहीं है। इस पर विचार करते हुए, वीएनआईटी के सिविल विभाग के प्रो. राहु रालेगांवकर ने कहा कि कृत्रिम रेत के उत्पादन के अलावा कोई अन्य व्यवहार्य विकल्प उपलब्ध नहीं है। विश्व के कई शोधकर्ताओं ने कृत्रिम रेत को प्रमाणित किया है और कहा है कि इसके अधिकतम उपयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने समझाया कि हम सभी को कृत्रिम रेत पर ज़ोर देना चाहिए। जिला खनन अधिकारी डॉ. अतुल डोड ने प्रारंभ में सभी गणमान्यों का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती प्रीति चुटे ने किया। इस संगोष्ठी में निर्माण क्षेत्र के कई उद्यमी उपस्थित थे।

5 ज्योतिर्लिंग विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अधिकारियों की नियुक्ति

मुंबई – राज्य के पाँच ज्योतिर्लिंगों की विकास योजनाओं के प्रभावी और त्वरित क्रियान्वयन हेतु पाँच वरिष्ठ सनदी अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। यह नियुक्ति मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देशानुसार की गई है। ये अधिकारी संबंधित ज्योतिर्लिंगों की विकास योजनाओं के कार्यों की नियमित समीक्षा करेंगे और मुख्यमंत्री फडणवीस को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। राज्य के पाँच ज्योतिर्लिंगों के विकास हेतु योजनाएँ तैयार की गई हैं। इन योजनाओं का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए इन अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। ज्योतिर्लिंगों एवं उनकी विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु नियुक्त अधिकारी इस प्रकार हैं - श्री क्षेत्र भीमाशंकर (जिला पुणे) – सामान्य प्रशासन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती. वी. राधा., श्री क्षेत्र घृष्णेश्वर (छत्रपति संभाजीनगर जिला) - अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग बी वेणुगोपाल रेड्डी। श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर (जिला नासिक) - वित्त विभाग के प्रधान सचिव श्री. -सौरभ विजय. श्री क्षेत्र औंधा नागनाथ (हिंगोली जिला) - वित्त विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती ऋचा बागला। श्री क्षेत्र परली वैजनाथ (बीड जिला) - अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सचिव अप्पासाहेब धुलज। इन पांचों ज्योतिर्लिंगों की तीर्थ विकास योजनाओं को उच्च स्तरीय समितियों की बैठकों में मंजूरी दी गई है। तदनुसार, समय-समय पर सरकारी निर्णय भी लिए गए हैं। तदनुसार, श्री क्षेत्र भीमाशंकर तीर्थ विकास योजना में 148 करोड़ 37 लाख रुपये के लगभग 11 कार्यों को मंजूरी दी गई है। श्री क्षेत्र घृष्णेश्वर तीर्थ विकास योजना 156 करोड़ 63 लाख रुपये की है। श्री क्षेत्र औंढा नागनाथ तीर्थ विकास योजना में 275 करोड़ रुपये के कार्यों को मंजूरी दी गई है, जिसकी लागत 15 करोड़ 21 लाख रुपये है। जबकि श्री क्षेत्र परली वैजनाथ तीर्थ विकास योजना में 286 करोड़ 68 लाख रुपये के 92 कार्यों को मंजूरी दी गई है।

मैंग्रोव क्षति और अनधिकृत निर्माण मामले में करें कार्रवाई

मुंबई – विधानसभा उपाध्यक्ष अन्ना बनसोडे ने संबंधित विभागों और एजेंसियों को अलीबाग क्षेत्र में कुछ कंपनियों द्वारा किए जा रहे मैंग्रोव वन को नुकसान पहुंचाने और अनधिकृत निर्माण के मामलों को गंभीरता से लेने और इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया

है। इस संबंध में विधान भवन के सभागार में एक बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर विधायक सुनील प्रभु और संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। विधानसभा उपाध्यक्ष श्री बनसोडे ने यह भी निर्देश दिया कि पर्यावरण एवं वन विभाग के कानूनों का उल्लंघन कर अनाधिकृत निर्माण और मैंग्रोव वनों को नुकसान पहुंचाने में शामिल कंपनियों के संबंध में गंभीरता से संज्ञान लिया गया है तथा संबंधित विभाग और एजेंसियां इस संबंध में तत्काल कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे ने कंदलवन वृक्ष कटाई मामले में संबंधित विभाग और एजेंसियों को संबंधित कंपनी के खिलाफ की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इस संबंध में विधान भवन के सभाकक्ष में एक बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर विधायक सना मलिक शेख, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अधिकारी ए.एन. खत्री, अधीक्षण अभियंता एस.एस. सराफ, कार्यकारी अभियंता एन.एस. देवरुखकर और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

विधानसभा उपाध्यक्ष श्री बनसोड़े ने कहा कि कंपनी द्वारा बिना अनुमति के मैंग्रोव वन में पेड़ों की कटाई का मुद्दा मानसून सत्र में उठाया गया था। इस संबंध में संबंधित विभाग और एजेंसियां इस मामले की गहन जांच कर तुरंत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

अल्पसंख्यक विद्यालयों में छात्रों की सुरक्षा के लिए समितियां गठित करें

ागपुर में आयोग की सुनवाई के दौरान अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने दिए निर्देश

नागपुर – महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान की अध्यक्षता में आज नियाज भवन में अल्पसंख्यक विद्यालयों के निदेशकों, प्राचार्यों और संबंधित अधिकारियों की एक विशेष बैठक हुई। इस बैठक में विद्यालयों में छात्रों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा की गई और संबंधित सरकारी निर्णय को जल्द से जल्द लागू करने के निर्देश दिए गए। छात्रों की सुरक्षा किसी भी विद्यालय की प्राथमिक ज़िम्मेदारी है। इस अवसर पर श्री खान ने कहा कि सभी अल्पसंख्यक विद्यालय 7 दिनों के भीतर आवश्यक समितियों का गठन करें और रिपोर्ट स्कूल शिक्षा विभाग को प्रस्तुत करें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। सरकार के निर्णय के अनुसार, प्रत्येक विद्यालय में एक विद्यालय प्रबंधन समिति, महिला शिकायत निवारण समिति, छात्र

सुरक्षा समिति और भौतिक सुविधा विकास समिति का गठन अनिवार्य है। ये समितियाँ विद्यालय प्रबंधन में पारदर्शिता लाने और कदाचार रोकने के लिए आवश्यक हैं। इस अवसर पर श्री खान ने कहा कि इस कार्यान्वयन में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बैठक में माध्यमिक शिक्षा अधिकारी निखिल भोयर, उप जिला कलेक्टर सचिन गोसावी, अधीक्षक सचिन नाथ, स्कूल शिक्षा विभाग के जिला बाल संरक्षण समन्वयक प्रसनजीत गायकवाड़, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पदाधिकारी मुश्ताक पठान, गणेश सुरवसे और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में कई प्राचार्यों ने स्कूल संचालन, परीक्षा संबंधी समस्याओं और भाषाई अल्पसंख्यक स्कूलों के लिए धन की मांग उठाई। प्राचार्यों द्वारा उठाए गए प्रश्न जायज हैं। श्री खान ने इस अवसर पर कहा कि वे स्वयं मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से चर्चा करेंगे और धन तथा नीतिगत समस्याओं को दूर करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करेंगे। इस बीच, उसी दिन नागपुर में अल्पसंख्यक आयोग द्वारा लंबित शिकायतों पर सुनवाई की गई। विदर्भ में कई मामलों में सीधे निर्णय दिए गए।

CC MM YY KK

संपादक की कलम से

डोभाल-पुतिन मुलाकात

डोभाल की यात्रा ऐसे समय में हुई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश जारी करके रूस से तेल खरीदने पर भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगाया है। इसके बाद कुल शुल्क 50 फीसदी हो गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन से मुलाकात करने के बाद अब प्रथम रूसी उपप्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता की है। यह वार्ता भारत और रूस के बीच सैन्य-तकनीकी संबंधों और रणनीतिक क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर आधारित रही। इसके अलावा वैश्विक स्तर के मामलों व भारत-रूस के रणनीतिक संबंधों को मजबूती देने के इरादे से भी इस बैठक को आयोजित किया गया। डोभाल द्विपक्षीय ऊर्जा और रक्षा संबंधों पर महत्वपूर्ण वार्ता करने और इस वर्ष के अंत में राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा की तैयारी के लिए रूस में हैं।

मिलिंद दहिवले
संपादक

कर्तव्य भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का संबोधन

क्रांति का महीना अगस्त, और 15 अगस्त से पहले ये ऐतिहासिक अवसर, हम एक के बाद एक आधुनिक भारत के निर्माण से जुड़ी उपलब्धियों के साक्षी बन रहे हैं। यहां राजधानी दिल्ली में ही कर्तव्य पथ, देश का नया संसद भवन, नया रक्षा भवन, भारत मंडपम्, यशोभूमि, शहीदों को समर्पित नेशनल वॉर मेमोरियल, नेताजी सुभाष बाबू की प्रतिमा और अब ये कर्तव्य भवन। ये केवल कुछ नए भवन और सामान्य इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हैं, अमृतकाल में इन्हीं भवनों में विकसित भारत की नीतियां बनेंगी, विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण निर्णय होंगे, आने वाले दशकों में यहीं से राष्ट्र की दिशा तय होगी। मैं आप सभी को, और सभी देशवासियों को कर्तव्य भवन की बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। मैं इसके निर्माण से जुड़े सभी इंजीनियर्स और सभी श्रमिक साथियों का भी आज इस मंच से धन्यवाद करता हूँ। हमने इस इमारत को बहुत मंथन के बाद 'कर्तव्य भवन' नाम दिया है। कर्तव्य पथ, कर्तव्य भवन, ये नाम हमारे लोकतंत्र की, हमारे संविधान की मूल भावना का उद्घोष करते हैं। गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है- न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन, नान-वाप्तं अ-वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि॥ अर्थात्, हमें क्या प्राप्त करना है, क्या प्राप्त नहीं करना है, इस सोच से ऊपर उठकर हमें कर्तव्य भाव से कर्म करना चाहिए। कर्तव्य, भारतीय संस्कृति में ये शब्द केवल दायित्व या responsibility तक सीमित नहीं हैं। कर्तव्य, हमारे देश के कर्मप्रधान दर्शन की मूल भावना है। स्व की सीमा से परे, सर्वस्व को स्वीकार करने की विराट दृष्टि, यही कर्तव्य की वास्तविक परिभाषा है। और इसलिए, कर्तव्य, ये सिर्फ इमारत का नाम भर नहीं है। ये करोड़ों देशवासियों के सपनों को साकार करने की तपोभूमि है। कर्तव्य ही आरंभ है, कर्तव्य ही प्रारब्ध है। करुणा और कर्मठता के स्नेह सूत्र में बंधा कर्म, वही तो है - कर्तव्य। सपनों का साथ है- कर्तव्य, संकल्पों की आस है- कर्तव्य, परिश्रम की पराकाष्ठा है- कर्तव्य, हर जीवन में ज्योत जला दे, वो इच्छाशक्ति है- कर्तव्य। करोड़ों देशवासियों के अधिकारों की रक्षा का आधार है- कर्तव्य, मां भारती की प्राण-ऊर्जा का ध्वजवाहक है- कर्तव्य, नागरिक देवो भव: के मंत्र का जाप है- कर्तव्य, राष्ट्र के प्रति भक्ति भाव से किया हर कार्य है- कर्तव्य।

आजादी के बाद दशकों तक देश की Administrative machinery उन बिल्डिंगों से चलाई जाती रही है, जो ब्रिटिश शासनकाल में बनी थी। आप भी जानते हैं, दशकों पहले बने इन प्रशासनिक भवनों में वर्किंग कंडीशन कितनी खराब, और अभी video में कुछ झलक भी देखी हमने। यहाँ काम करने वालों के लिए ना पर्याप्त स्पेस है, ना रोशनी है, ना जरूरी वेंटिलेशन है। आप कल्पना कर सकते हैं, होम मिनिस्ट्री जैसी महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री करीब 100 साल से एक ही बिल्डिंग में अपर्याप्त संसाधनों के साथ चल रही थी। इतना ही नहीं, भारत सरकार के अलग-अलग मंत्रालय, दिल्ली के 50 अलग-अलग जगहों से चल रहे हैं, इनमें से बहुत सारे मंत्रालय तो किराए की बिल्डिंग में हैं। इनके किराए पर जितने रुपए खर्च हो रहे थे, वो अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। और वैसे पूरा हिसाब लगाए तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर मोटा-मोटा हिसाब लगाए तो डेढ़ हजार करोड़ रुपया प्रति वर्ष इसमें जाता है। इतनी बड़ी राशि भारत सरकार अलग-अलग मंत्रालयों के सिर्फ किराए पर खर्च कर रही है। इसके अलावा एक और दिक्कत। काम की वजह से स्वभाविक है कि कर्मचारियों का यहां से वहां आना-जाना भी होता है, अनुमान है कि हर रोज 8 से 10 हजार कर्मचारियों को एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में आना-जाना पड़ता है। अब इसमें भी सैकड़ों गाड़ियों का मूवमेंट होता है, खर्च होता है, सड़कों पर traffic बढ़ता है, कितना समय खराब होता है, और इन सबसे काम में भी inefficiency के सिवाय कुछ नहीं रहता है।

21वीं सदी के भारत को, 21वीं सदी की आधुनिक व्यवस्थाएं चाहिए, इमारतें भी चाहिए। ऐसी इमारतें जो टेक्नोलॉजी, सुरक्षा और सुविधा के लिहाज से बेहतरीन हो। जहां कर्मचारी सहज हों, फैसले तेज हों, और सेवाएं सुगम हों। इसलिए कर्तव्य पथ के आसपास एक holistic विज़न के साथ कर्तव्य भवन जैसी विशाल इमारतों का निर्माण किया जा रहा है। ये तो पहला कर्तव्य भवन पूरा हुआ है, अभी कई कर्तव्य भवनों का निर्माण तेजी से चल रहा है। ये ऑफिसेस जब आस-पास शिफ्ट होंगे, नजदीक-नजदीक हो जाएगी, तो इससे कर्मचारियों को सही work environment मिलेगा, जरूरी सुविधाएं मिलेंगी, उनका total work output भी बढ़ेगा। और सरकार जो डेढ़ हजार करोड़ किराए पर खर्च कर रही है, वो भी बचेगा।

कर्तव्य भवन की ये भव्य बिल्डिंग, ये सभी प्रोजेक्ट्स, नए डिफेंस कॉम्प्लेक्स, देश के तमाम बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ये देश के pace का सबूत तो हैं ही, ये भारत के वैश्विक विज़न का प्रतिबिंब भी हैं। हम दुनिया को जो विज़न दे रहे हैं, भारत खुद उन्हें किस तरह अंगीकार कर रहा है। ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर development में दिखाई दे रहा है। हमने दुनिया को मिशन LiFE दिया, हमने One Earth, One Sun, One Grid का आइडिया विश्व के सामने रखा, ये वो विज़न हैं, जिनसे मानवता के भविष्य की उम्मीद जुड़ी है। आज आप देख सकते हैं, कर्तव्य भवन जैसे हमारे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जिनकी आत्मा, Pro-people है। और इनका स्ट्रक्चर pro-planet है। कर्तव्य भवन में भी रूफटॉप पर सोलर पैनल्स लगाए गए हैं, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए advanced systems को इसमें integrate किया गया है। ग्रीन बिल्डिंग्स का विज़न अब भारत में विस्तार ले रहा है।

हमारी सरकार, एक होलिस्टिक विजन के साथ भारत के नव-निर्माण में जुटी है। देश का कोई भी हिस्सा आज विकास की धारा से अछूता नहीं है। अगर दिल्ली में संसद की नई इमारत बनी है, तो देश में 30 हजार से ज्यादा पंचायत भवन भी बने हैं। आज यहां एक ओर कर्तव्य भवन जैसी बिल्डिंग बन रही है, तो साथ ही गरीबों के लिए 4 करोड़ से ज्यादा पक्के घर भी बनाए गए हैं। यहां नेशनल वॉर मेमोरियल बना है, पुलिस मेमोरियल बना है, तो देश में 300 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज भी बनाए गए हैं। यहां भारत मंडपम बना है, तो देश में 1300 से ज्यादा नए अमृत भारत रेलवे स्टेशंस भी बनाए जा रहे हैं। यहां बने यशोभूमि की भव्यता पिछले 11 साल में बने करीब 90 नए एयरपोर्ट में भी नजर आती है। महात्मा गांधी कहते थे, अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।

60वें और 61वें राज्य सरकार के मराठी फिल्म पुरस्कार समारोह की हीरक जयंती उत्साह के साथ संपन्न

चित्रपति वी. शांताराम और स्वर्गीय राज कपूर पुरस्कारों का वितरण

मुंबई – अभिनेता-निर्देशक महेश मांजरेकर को चित्रपति वी. शांताराम लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि अभिनेत्री मुक्ता बर्वे को चित्रपति वी. शांताराम विशेष योगदान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वरिष्ठ अभिनेता अनुपम खेर को स्वर्गीय राज कपूर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि अभिनेत्री काजोल को स्वर्गीय राज कपूर विशेष योगदान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वयोवृद्ध गजल गायक भीमराव पंचाले को गान सम्राट लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि भारत के राजदूत और यूनेस्को में स्थायी प्रतिनिधि विशाल शर्मा को छत्रपति शिवाजी महाराज महावरसा पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

राज्य सरकार के सांस्कृतिक मामलों के विभाग द्वारा मराठी फिल्मों और फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए दिए जाने वाले राज्य मराठी फिल्म पुरस्कारों का हीरक जयंती संस्करण और पुरस्कार वितरण समारोह मंगलवार को मुंबई के डोम एसवीपी ऑडिटोरियम में बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर, 60वें और 61वें राज्य मराठी फिल्म पुरस्कारों के साथ-साथ वर्ष 2024 के लिए चित्रपति वी. शांताराम आजीवन उपलब्धि और विशेष योगदान पुरस्कार और स्वर्गीय राजकपूर आजीवन उपलब्धि और विशेष योगदान पुरस्कार वितरित किए गए। इस अवसर पर गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार और छत्रपति शिवाजी महाराज महावर्ष पुरस्कार भी वितरित किए गए। ये पुरस्कार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, सांस्कृतिक मामलों के मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार, मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा और राज्य मंत्री आशीष जायसवाल द्वारा प्रदान किए गए।

इस अवसर पर राजस्व एवं वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खड़गे, सांस्कृतिक कार्य विभाग की सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी, महाराष्ट्र फिल्म, रंगमंच एवं सांस्कृतिक विकास महामंडल की प्रबंध निदेशक स्वाति म्हसे-पाटिल, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय के निदेशक बिभीषण चावरे, महाराष्ट्र फिल्म, रंगमंच एवं सांस्कृतिक विकास महामंडल के संयुक्त प्रबंध निदेशक प्रशांत सजनीकर के साथ ही सांस्कृतिक कार्य विभाग के संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी, फिल्म निर्माता, फिल्म प्रेमी एवं मीडियाकर्मी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

सांस्कृतिक मामलों के विभाग और महाराष्ट्र फिल्म, रंगमंच और सांस्कृतिक विकास निगम द्वारा आयोजित 60वें और 61वें राज्य मराठी फिल्म पुरस्कार समारोह में, 2022 और 2023 में रिलीज होने वाली मराठी फिल्मों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विभिन्न कार्य समूहों की ओर से पुरस्कार वितरित किए गए। साथ ही, इस अवसर पर, अभिनेता-निर्देशक महेश मांजरेकर को चित्रपति वी. शांताराम लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और अभिनेत्री मुक्ता बर्वे को चित्रपति वी. शांताराम विशेष योगदान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही, अनुभवी अभिनेता अनुपम खेर को स्वर्गीय राज कपूर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और अभिनेत्री काजोल को स्वर्गीय राज कपूर विशेष योगदान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जबकि गान सम्राजी लता मंगेशकर पुरस्कार अनुभवी गजल गायक भीमराव पांचाले को प्रदान किया गया। साथ ही, इस वर्ष से, राज्य सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज के 12 किलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए 'छत्रपति शिवाजी महाराज महावर्ष पुरस्कार' शुरू किया है। यह पुरस्कार यूनेस्को में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि विशाल शर्मा को तथा अखिल महाराष्ट्र पर्वतारोहण महासंघ को प्रदान किया गया, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के किलों के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रयासरत है।

60वें महाराष्ट्र राज्य मराठी फिल्म पुरस्कार – 2022

1. सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन - महेश कुडालकर (उनाद)
2. सर्वश्रेष्ठ छायांकन - अभिजीत चौधरी / ओंकार बर्वे (4 ब्लाइंड मेन) और प्रियशंकर घोष (दिस थिंग हैज़ नो नेम)
3. उत्कृष्ट संकलन - एस सुर्वे - (काटा किर्रर्र)
4. सर्वश्रेष्ठ ध्वनि रिकॉर्डिंग - सुभाष किशोर राणे (इस चीज़ का कोई नाम नहीं है)
5. बेहतरीन साउंड मिक्सिंग - लोचन प्रताप कनविंदे - हर हर महादेव
6. सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिज़ाइन - उज्ज्वला सिंह - स्टिफ
7. सर्वश्रेष्ठ मेकअप - सुमेध जाधव/सौरभ कपाडे - स्टिफ
8. सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार - श्रीनिवास पोकले (छुमंतर) / अर्नव देशपांडे (अमी बटरफ्लाई)
9. सर्वश्रेष्ठ कहानी - सुमीत तांबे (समीरा)
10. सर्वश्रेष्ठ पटकथा - तेजस मोदक - सचिन कुंडलकर (पांडिचेरी)
11. सर्वश्रेष्ठ संवाद - प्रवीण तारडे (धर्मवीर मुक्कम पोस्ट ठाणे)
12. सर्वश्रेष्ठ गीत - अभिषेक खांकर - (अनन्या - गीत - धागा आद या)
13. सर्वश्रेष्ठ पृष्ठभूमि संगीत - हनी सातमकर (अटूर)
14. सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक - मनीष राजगिरे (धर्मवीर मुक्कम पोस्ट ठाणे गीत - मेट विट्ठल माजा)
15. सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक (विभाजित) - आर्य अंबेकर (चंद्रमुखी) और अमित घुघरी (सोयरिक)
16. सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर - उमेश जाधव (धर्मवीर मुक्कम पोस्ट ठाणे - गाना - आई जगदंबे)
17. उत्कृष्ट संगीत - निहार स्कीमबेकर (समायरा)
18. सहायक अभिनेता - योगेश सोमन - (अनन्या)
19. सहायक अभिनेत्री - मृण्मयी देशपांडे (चंद्रमुखी)
20. सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता - संजय नार्वेकर (टाइमपास 3)
21. सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता - जयदीप कोडोलिकर (इस चीज़ का कोई नाम नहीं है)
22. सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री - रीता दुर्गुले (अनन्या)
23. सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री - अमृता खानविलकर (चंद्रमुखी) साई ताम्हणकर (पांडिचेरी)
24. सर्वश्रेष्ठ अभिनेता - प्रसाद ओक (धर्मवीर मुक्कम पोस्ट ठाणे)
25. पहली डेब्यू फिल्म निर्माण - जेनिथ फिल्म्स (अटूर)
26. प्रथम डेब्यू फिल्म निर्देशक - प्रताप फाड़ (अनन्या)
27. सामाजिक मुद्दों से जुड़ी एक फिल्म - समायरा
28. सामाजिक मुद्दों को उठाने वाले फिल्म निर्देशक - ऋषि देशपांडे
29. ग्रामीण मुद्दों से संबंधित एक फिल्म - गाभ
30. ग्रामीण मुद्दों को उठाने वाले फिल्म निर्देशक – अनूप जतराटकर
31. सर्वश्रेष्ठ फिल्म नंबर 1 - धर्मवीर मुक्कम पोस्ट ठाणे
32. सर्वश्रेष्ठ निर्देशक नंबर 1 - प्रवीण तारडे
33. सर्वश्रेष्ठ फिल्म नंबर 2 - पांडिचेरी
34. सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक नंबर 2 - सचिन कुंडलकर
35. सर्वश्रेष्ठ फिल्म नंबर 3 - हर हर महादेव
36. सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक नंबर 3 – अभिजीत देशपांडे

61वें राज्य मराठी फिल्म पुरस्कार के विजेता

(1) सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन - अमेय भालेराव (श्याम की माँ)
(2) सर्वश्रेष्ठ छायांकन - जिप्सी (प्रवीण सोनावणे)
(3) सर्वश्रेष्ठ संकलन – जिप्सी (अक्षय शिंदे)
(4) सर्वश्रेष्ठ ध्वनि रिकॉर्डिंग - कुणाल लोलसुरे (श्याम की माँ)
(5) सर्वश्रेष्ठ साउंड मिक्सिंग - विकास खंडारे (जिप्सी)
(6) सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइन - मानसी अटार्डे (जग्गू और जूलियट)
(7) सर्वश्रेष्ठ मेकअप - हामिद शेख और मनाली भोसले (वह शख्स जिसने शोले को हज़ार बार देखा है)
(8) सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार (विभाजित) - कबीर खंडारे और तृषा ठोसर (नाल 2)
(9) उत्कृष्ट कहानी – सुधाकर रेड्डी (Nal 2)
(10) सर्वश्रेष्ठ पटकथा - शशि चंद्रकांत खंडारे (जिप्सी)
(11) सर्वश्रेष्ठ संवाद - अंबर हडप और गणेश पंडित (जग्गू और जूलियट)
(12) उत्कृष्ट गीत - वैभव देशमुख (नाल 2 - गरगारा भिंगोरी)
(13) सर्वश्रेष्ठ पृष्ठभूमि संगीत - अद्वैत नेमलेकर (नल 2)
(14) सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक - मोहित चौहान (घर, बंदूक, बिरयानी)
(15) सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका - ऋचा बोंद्रे (श्याम की माँ)
(16) सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी - राहुल थोम्ब्रे और संजीर हलदार (जग्गू और जूलियट)
(17) सर्वश्रेष्ठ संगीत - अजय-अतुल (महाराष्ट्र शहीर)
(18) सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता - संतोष जुवेकर (रावरम्भा)
(19) सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री - उषा नाइक (आशा)
(20) सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता - उपेन्द्र लिमये (जग्गू और जूलियट)
(21) सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेत्री - निर्मला सावंत (जिम्मा 2)
(22) सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता - दीपक जोइल (भेरा) उत्कृष्ट
(23) पहली डेब्यू अभिनेत्री (विभाजित) - श्रद्धा खानोलकर (भेरा) और गौरी देशपांडे (श्याम की माँ)
(24) सर्वश्रेष्ठ अभिनेता - अमेय वाघ (जग्गू और जूलियट)
(25) सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री - रिंकू राजगुरु (आशा)
(26) सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म निर्देशक - आशीष बेंडे (आत्मकथा)
(27) सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म निर्माण - टॉक शो प्रोडक्शन (जिप्सी)
(28) सर्वश्रेष्ठ सामाजिक मुद्दे वाली फिल्म - आशा
(29) उत्कृष्ट सामाजिक मुद्दों पर काम करने वाले निर्देशक - दीपक पाटिल
(30) ग्रामीण मुद्दों पर आधारित सर्वश्रेष्ठ फिल्म - जिप्सी
(31) ग्रामीण मुद्दों को बखूबी संभालने वाली निर्देशक - शशि खंडारे
(32) सर्वश्रेष्ठ फिल्म नंबर 1 - भेरा
(33) सर्वश्रेष्ठ निर्देशक - श्रीकांत प्रभाकर भिड़े
(34) सर्वश्रेष्ठ फिल्म नंबर 2 - जग्गू एंड जूलियट
(35) सर्वश्रेष्ठ निर्देशक नंबर 2 - महेश लिमये
(36) सर्वश्रेष्ठ फिल्म नंबर 3 - नाल 2
(37) सर्वश्रेष्ठ निर्देशक नंबर 3 - सुधाकर वेंकटती रेड्डी
(38) विशेष बाल कलाकार पुरस्कार-भार्गव जगताप (नल 2)

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म श्यामची आई को सम्मानित किया गया।

यह पत्र मालक, मुद्रक, प्रकाशक मिलिंद दहीवले ने एम.पी.ऑफसेट सिरसपेठ चौक, उमरेड़ रोड, नागपुर यहां से मुद्रित कर कार्यालय - फ्लैट नंबर 204, दूसरा माला, साकेत अपार्टमेंट, फूलमती ले-आउट, आरोग्यम क्लीनिक के पास, नागपुर-440027 से प्रकाशित किया. मिलिंद दहीवले, मो.9552011005. email : manvadhikar2012@gmail.com वेबसाईट: www.kendriyamanvadhikar.com

This paper is printed by owner, printer and publisher Milind Dahiwale at MP Offset, Siraspeth Chowk, Umred Road, Nagpur and published from office Flat No. 204, Second Floor, Saket Apartment, Phulmati Layout, Near Arogya Clinic, Nagpur 440027. Milind Dahiwale Mobile No. 9552011005. email : manvadhikar2012@gmail.com वेबसाईट: www.kendriyamanvadhikar.com

केन्द्रीय मानवाधिकार समाचार पत्र में प्रकाशित सभी लेख, छायाचित्र पर संपादक की सहमति हो, यह आवश्यक नहीं है। न्यायिक कार्यवाही केवल नागपुर न्यायालय में होगी।

न्यूज गैलरी

खैबर पख्तूनख्वा में अज्ञात आतंकी ने 4 पाक जवानों को मार डाला

खैबर पख्तूनख्वा – पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने एक बार फिर सुरक्षा बलों को निशाना बनाया है। घात लगाकर किए गए हमले में अज्ञात हमलावरों ने अर्द्धसैनिक बल के चार जवानों को मार डाला है। पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिम खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बुधवार को अज्ञात बंदूकधारियों ने अर्द्धसैनिक बल 'फ्रंटियर कांस्टेबुलरी' के कम से कम चार जवानों की हत्या कर दी है। पुलिस ने इस बारे में जानकारी दी है। हमलावरों ने करक जिले के अमन कोट तोई इलाके में फ्रंटियर कांस्टेबुलरी (एफसी) के एक वाहन पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें चार जवान मारे गए। सुरक्षा बलों और पुलिस ने तुरंत इलाके की घेराबंदी की और हमलावरों को पकड़ने के लिए तलाश अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस के एक अधिकारी ने संकेत दिया कि हमला पूर्व नियोजित था और हमलावर घात लगाए बैठे थे। अब तक किसी भी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने हमले की कड़ी निंदा की है और संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदार लोगों को पकड़ने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षा कर्मियों पर यह कोई पहला हमला नहीं है। यहां अज्ञात बंदूकधारियों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। हाल ही में अज्ञात बंदूकधारियों ने 'फ्रंटियर कॉर्प्स' के एक वाहन पर घात लगाकर हमला किया था। इस दौरान हुई गोलीबारी में एक सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई थी जबकि एक अन्य घायल हो गया था। यह हमला बन्नू जिले में हुआ था उत्तर वजीरिस्तान से सटा हुआ है। इस बीच यहां यह भी बता दें कि, हाल ही में दक्षिण-पश्चिमी पाकिस्तान में बंदूकों और रॉकेट से लैस कई हमलावरों ने एक पुलिस थाने पर हमला कर दिया था और फिर 2 बैंकों में आग लगा दी था। इस हमले में एक लड़के की मौत हो गई थी और 9 अन्य लोग घायल हुए थे। यह हमला बलूचिस्तान प्रांत के मस्तुंग जिले में हुआ था।

पाकिस्तानी सेना ने बलूच आर्मी के सामने सरेंडर किया

बलूचिस्तान – पाकिस्तानी सेना ने बलूच आर्मी के सामने सरेंडर कर दिया है। एक वीडियो में पाकिस्तानी सैनिक बलूचिस्तान से मैदान छोड़कर भागते दिख रहे हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना को बलूचिस्तान लिब्रेशन आर्मी (बीएलए) के लड़ाकों के सामने मैदान छोड़कर भागना पड़ा है। बलोच नेता मीर यार बलोच ने जंग के मैदान से जान बचाकर भागती पाकिस्तानी सेना का एक वीडियो जारी किया है। यह वीडियो देखकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा हाल ही में फील्ड मार्शल का झूठा तमगा हासिल करने वाले पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर का सिर भी शर्म से झुक जाएगा। अपनी सेना की ऐसी कायरता को देखकर वह अब दुनिया के सामने मुंह नहीं दिखा पाएंगे। बलूचिस्तान से भागते पाकिस्तानी सैनिकों का एक वीडियो बलोच नेता मीर यार बलोच ने अपने एक्स एकाउंट पर शेयर किया है, जिसमें पाकिस्तानी सैनिक जंग के मैदान को छोड़कर पूंछ दबाकर भागते दिख रहे हैं। मीर यार बलोच ने लिखा, "पाकिस्तान की कायर सेना भाग रही है और बलूचिस्तान में अपनी चौकियों को छोड़ रही है। देखिए, किस तरह बलूचिस्तान के स्वतंत्रता सेनानी पाकिस्तान की कब्ज़ा करने वाली सेना को युद्ध के मैदान में पीछे धकेल रहे हैं।" बलूचिस्तान के लड़ाकों से भिडंत के बाद एक महीने के लिए पूरे बलूचिस्तान में एक महीने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। बलोच नेता ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि दुश्मन ने पूरे देश में एक महीने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया है।"

रक्षाबंधन एवं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नागपुर मंडल में 12 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा मध्य रेल

रक्षाबंधन एवं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लंबी छुट्टियों के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए, मध्य रेल नागपुर मंडल में 12 विशेष रेलगाड़ियाँ चलाएगा। इनमें छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) और नागपुर के बीच 6 सेवाएँ, तथा पुणे और नागपुर के बीच 6 सेवाएँ शामिल हैं। विवरण इस प्रकार है : CSMT – नागपुर विशेष रेलगाड़ियाँ (2 सेवाएँ) गाड़ी संख्या 01123 विशेष ट्रेन 09.08.2025 को 00.20 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई से रवाना होकर उसी दिन 15.30 बजे नागपुर पहुँचेगी (1 सेवा)। गाड़ी संख्या 01124 विशेष ट्रेन 10.08.2025 को 14.30 बजे नागपुर से रवाना होकर अगले दिन 05.25 बजे CSMT, मुंबई पहुँचेगी(1 सेवा)। ठहराव: दादर, ठाणे, कल्याण, इगतपुरी, नासिक रोड, मनमाड, जलगांव, भुसावल, मलकापुर, शेगांव, अकोला, मुर्तिजापुर, बडनेरा, धामनगांव और वर्धा। कोच संरचना: 2 एसी तृतीय श्रेणी, 12 शयनयान, 6 सामान्य द्वितीय श्रेणी, एवं 2 द्वितीय आसन युक्त गार्ड ब्रेक वैन।

CSMT–नागपुर विशेष रेल (4 सेवाएँ) गाड़ी संख्या 02139 विशेष ट्रेन 15.08.2025 और 17.08.2025 को 00.20 बजे CSMT, मुंबई से रवाना होकर उसी दिन 15.30 बजे नागपुर पहुँचेगी (2 सेवाएँ)। गाड़ी संख्या 02140 विशेष ट्रेन 15.08.2025 और 17.08.2025 को 20.00 बजे नागपुर से रवाना होकर अगले दिन 13.30 बजे CSMT, मुंबई पहुँचेगी (2 सेवाएँ)। ठहराव: दादर, ठाणे, कल्याण, इगतपुरी, नासिक रोड, मनमाड, जलगांव, भुसावल, मलकापुर, शेगांव, अकोला, मुर्तिजापुर, बडनेरा, धामनगांव और वर्धा। कोच संरचना: समान – 2 एसी तृतीय श्रेणी, 12 शयनयान, 6 सामान्य द्वितीय श्रेणी, एवं 2 द्वितीय आसन युक्त गार्ड ब्रेक वैन। पुणे – नागपुर विशेष रेलगाड़ियाँ (2 सेवाएँ) गाड़ी संख्या 01469 विशेष ट्रेन 08.08.2025 को 19.55 बजे पुणे से रवाना होकर अगले दिन 14.45 बजे नागपुर पहुँचेगी (1 सेवा)। गाड़ी संख्या 01470 विशेष ट्रेन 10.08.2025 को 13.00 बजे नागपुर से रवाना होकर अगले दिन 05.20 बजे पुणे पहुँचेगी (1 सेवा)। ठहराव: दौंड कॉर्ड लाइन, अहमदनगर, कोपरगांव, मनमाड, जलगांव, भुसावल, मलकापुर, शेगांव, अकोला, बडनेरा, और वर्धा। कोच संरचना: 2 एसी तृतीय श्रेणी, 12 शयनयान, 6 सामान्य द्वितीय श्रेणी, एवं 2 द्वितीय आसन युक्त गार्ड ब्रेक वैन। पुणे – नागपुर विशेष रेलगाड़ियाँ (4 सेवाएँ) गाड़ी संख्या 01439 विशेष ट्रेन 14.08.2025 और 16.08.2025 को 19.55 बजे पुणे से रवाना होकर अगले दिन 14.45 बजे नागपुर पहुँचेगी (2 सेवाएँ)। गाड़ी संख्या 01440 विशेष ट्रेन 15.08.2025 और 17.08.2025 को 16.15 बजे नागपुर से रवाना होकर अगले दिन 07.20 बजे पुणे पहुँचेगी (2 सेवाएँ)। ठहराव और कोच संरचना: दौंड कॉर्ड लाइन, अहमदनगर, कोपरगांव, मनमाड, जलगांव, भुसावल, मलकापुर, शेगांव, अकोला, बडनेरा और वर्धा। आरक्षण विवरण: इन विशेष गाड़ियों के लिए आरक्षण सभी कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्रों तथा वेबसाइट www.irctc.co.in पर निम्नानुसार आरंभ होगा: गाड़ी संख्या 01123, 01124, 01469, 01470 – आरक्षण 07.08.2025 से शुरू होगा। संख्या 02139, 02140, 01439, 01440, 01125, 01127 – आरक्षण 09.08.2025 से शुरू होगा। इन विशेष गाड़ियों के स्टेशनों पर विस्तृत समय सारिणी देखने के लिए कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाएँ या NTES ऐप डाउनलोड करें। यह विज्ञप्ति मध्य रेल, नागपुर मंडल के जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी की गई है।

विदर्भ, तापी, कोंकण सिंचाई विकास निगम नियामक बोर्ड की बैठक

मुंबई – जल संसाधन (विदर्भ, तापी, कोंकण सिंचाई विकास महामंडल) और आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीश महाजन ने निर्देश दिए हैं कि राज्य में सिंचाई क्षेत्र बढ़ाने और कृषि के लिए सतत जल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्माणाधीन परियोजनाओं का काम तीव्र गति से और समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन की अध्यक्षता में मंत्रालय में विदर्भ, तापी और कोंकण सिंचाई विकास निगम के शासी मंडल की बैठक हुई। इस अवसर पर वे बोल रहे थे। बैठक में जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कपूर, सचिव संजय बेलसरे, विदर्भ सिंचाई विकास निगम के कार्यकारी निदेशक राजेश सोनटक्के, तापी सिंचाई विकास निगम के कार्यकारी निदेशक जे.डी. बोरकर, कोंकण सिंचाई विकास निगम के कार्यकारी निदेशक अतुल कपोले और जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। नियामक मंडल की बैठक में स्वीकृत कार्यों से सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि होगी। तदनुसार, इन कार्यों की योजना बनाकर उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। साथ ही, जल पट्टियों की बहाली के लिए भी विभाग सावधानीपूर्वक योजना बनाए और तदनुसार कार्रवाई करे, यह निर्देश भी जल संसाधन मंत्री श्री महाजन ने इस अवसर पर दिए। विदर्भ सिंचाई विकास निगम के शासी मंडल की 87वीं बैठक में 42 विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई, तापी सिंचाई विकास बोर्ड के शासी मंडल की 71वीं बैठक में 25 विषयों पर चर्चा हुई, तथा कोंकण सिंचाई विकास निगम के शासी मंडल की 88वीं बैठक में 18 विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।

लोस अध्यक्ष ने डॉ. ढिल्लों को पुष्पांजलि अर्पित की

नई दिल्ली – लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने पूर्व लोक सभा अध्यक्ष, डॉ. जी. एस. ढिल्लों की जयंती पर संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत; राज्य सभा के उपसभापति, श्री हरिवंश, संसद सदस्यों, पूर्व सदस्यों, लोक सभा के महासचिव, श्री उत्पल कुमार सिंह; राज्य सभा के महासचिव, श्री पी.सी. मोदी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी डॉ. ढिल्लों को श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉ. ढिल्लों 8 अगस्त 1969 से 17 मार्च 1971 तक और 22 मार्च 1971 से 1 दिसंबर 1975 तक लोक सभा अध्यक्ष रहे। उन्होंने 1 दिसंबर 1975 को अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और केंद्रीय मंत्रिमंडल में पोत परिवहन एवं सड़क परिवहन मंत्री बने। वे 12 मई 1986 से 14 फरवरी 1988 तक कृषि मंत्री रहे। अपनी लंबी और विशिष्ट सेवा के दौरान, डॉ. ढिल्लों ने योजना आयोग के सदस्य और कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त सहित कई अन्य प्रमुख पदों पर भी कार्य किया। 23 मार्च 1992 को उनका देहावसान हो गया।

भारत में आधुनिक पोत परिवहन के लिए दोहरा समर्थन - सोनोवाल

लोकसभा से आधुनिक और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समन्वित नीति के लिए 'व्यापारिक पोत परिवहन विधेयक, 2025' पारित होने के साथ भारत ने समुद्री ढाँचे को अद्यतन किया। राज्यसभा ने व्यापार सुगमता और भारत के पोत परिवहन क्षेत्र को भविष्य के लिए तैयार करने हेतु 'समुद्री माल परिवहन विधेयक, 2025' पारित किया। संसद ने ऐतिहासिक घटनाक्रम में बुधवार को दो ऐतिहासिक समुद्री विधेयक पारित किए। पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) के लिए यह पहला विधेयक है। इससे भारत में आधुनिक, कुशल और वैश्विक स्तर पर समन्वित समुद्री नीति ढाँचे का मार्ग प्रशस्त हुआ। लोकसभा ने 'व्यापारिक पोत परिवहन विधेयक, 2025' को स्वीकृति दे दी। इसका उद्देश्य आधुनिक और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनुपालन दृष्टिकोण के साथ समुद्री शासन को सुव्यवस्थित करना है। इस बीच, राज्यसभा ने 'समुद्री माल ढुलाई विधेयक, 2025' पारित किया। इसने एक सदी पुराने औपनिवेशिक युग के कानून को व्यापार में आसानी को बढ़ावा देने और भारत के नौवहन क्षेत्र को भविष्य के लिए तैयार करने हेतु डिज़ाइन किए गए अद्यतन कानून से बदल दिया।

इस अवसर पर केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, "आज मंत्रालय में हम सभी के लिए ऐतिहासिक दिन है। संसद ने दो महत्वपूर्ण विधेयकों - व्यापारिक पोत परिवहन विधेयक, 2025 और समुद्री माल ढुलाई विधेयक, 2025 - को पारित किया है, जो नीतिगत और कार्यान्वयन दोनों दृष्टि से भारत के समुद्री क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दृष्टिकोण का प्रभावी ढंग से समर्थन करते हैं। आज, इन विधेयकों के पारित होने के साथ, भारत के आधुनिक पोत परिवहन के लिए मोदी सरकार के प्रयासों को संसद से दोहरा समर्थन प्राप्त हुआ है।"

व्यापारिक पोत परिवहन विधेयक, 2025 - प्रगतिशील, भविष्य के लिए तैयार कानून जो पुराने व्यापारिक पोत परिवहन अधिनियम 1958 का स्थान लेगा। यह विधेयक भारत के समुद्री कानूनी ढांचे को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने और विश्वसनीय समुद्री व्यापार केंद्र के रूप में देश की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। लोकसभा में व्यापारिक पोत परिवहन विधेयक, 2025 पेश करते हुए, केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, "यह विधेयक भारत को समुद्री व्यापार और प्रशासन में वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करने की दिशा में निर्णायक कदम है। यह प्रगतिशील और उन्नत कानून है, जो अंतरराष्ट्रीय समुद्री सम्मेलनों के अनुरूप है और अग्रणी समुद्री राष्ट्रों की सर्वोत्तम प्रथाओं से प्रेरित है।" यह विधेयक प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में किए गए प्रमुख कानूनी सुधारों की श्रृंखला का हिस्सा है। इसका उद्देश्य शिपिंग और समुद्री क्षेत्रों में मजबूत विकास को सक्षम बनाना है। इन सुधारों ने दक्षता, पारदर्शिता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में उल्लेखनीय वृद्धि की है। अद्यतन ढाँचे की आवश्यकता पर बल देते हुए, मंत्री ने कहा कि व्यापारिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 561 धाराओं के साथ भारी, खंडित और पुराना हो गया था, जो समकालीन समुद्री चुनौतियों का समाधान करने या कई प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन सम्मेलनों के तहत भारत के दायित्वों को पूरी तरह से लागू करने में विफल रहा। सर्बानंद सोनोवाल ने यह भी कहा, "व्यापारिक पोत परिवहन विधेयक, 2025, 16 भागों और 325 धाराओं के साथ, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के अनुरूप भारत के समुद्री कानूनी ढाँचे का आधुनिकीकरण करता है।

महाराष्ट्र जीएसटी विभाग ने फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट के दुरुपयोग और कर चोरी के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया

मुंबई – महाराष्ट्र माल और सेवा कर (जीएसटी) विभाग ने विनय राजेश पारेख (उम्र 37) निवास ए-402, कुंज पैराडाइज, आईआईसीआई बैंक के सामने, बड़ौदा, गुजरात 390002 को 29.88 करोड़ रुपये के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करके कर चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी मेसर्स एंजेल प्लाई एंड लैम फर्म के खिलाफ चल रही जाँच का हिस्सा है। विभाग ने ऐसे कर चोरों के खिलाफ एक विशेष अभियान शुरू किया है जो बिना किसी वस्तु या सेवा की आपूर्ति के फर्जी चालान तैयार करके अवैध रूप से आईटीसी का लाभ उठा रहे हैं। यह महाराष्ट्र/केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत एक गंभीर उल्लंघन है।

विनय राजेश पारेख मेसर्स एंजेल प्लाई एंड लैम नामक फर्म के मालिक हैं और उन्होंने इस फर्म के माध्यम से लगभग 29.88 करोड़ रुपये का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है। आरोपी विनय राजेश पारेख को गिरफ्तार कर माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट एस्प्लेनेड कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, जहाँ अदालत ने उन्हें 18 अगस्त, 2025 तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है।

उक्त कार्रवाई सहायक राज्य कर आयुक्त (डी-313) नितिन चंद्र जी. पाटिल और सहायक राज्य कर आयुक्त (डी-315) रमेश यू. आवेके के नेतृत्व में डीसी-ई-0303 इकाई के राज्य कर निरीक्षकों के साथ की गई। महाराष्ट्र जीएसटी विभाग ने एक बार फिर फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट के मामलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का संकल्प दोहराया है। राज्य कर विभाग सभी करदाताओं से जीएसटी कानूनों का सख्ती से पालन करने की अपील करता है और उन्हें किसी भी तरह की कर चोरी से दूर रहने की चेतावनी देता है। एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि फर्जी लेनदेन में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

अंगदान सर्जरी से कुछ समय पूर्व कोमा से जागी महिला, बच गई उसकी जान

अमेरिका – अमेरिका में एक महिला कोमा में थी। महिला की अंगदान सर्जरी होने वाली थी लेकिन उससे पहले ही कुछ ऐसा हुआ कि डॉक्टरों ने सर्जरी नहीं करने का फैसला लिया। चलिए पूरी घटना के बारे में जानते हैं। कभी-कभी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो किसी चमत्कार से कम नहीं लगती हैं। एक ऐसी ही घटना अमेरिका से सामने आई है। साल 2022 में 38 साल की एक बेघर महिला, डैनेला गैलेगोस, न्यू मैक्सिको के अल्बुकर्क स्थित प्रेस्बिटेरियन अस्पताल में एक अज्ञात चिकित्सा आपात स्थिति के बाद कोमा में चली गईं। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, डॉक्टरों ने उनके परिवार को बताया कि उनके ठीक होने की संभावना कम है, जिसके बाद वो न्यू मैक्सिको डोनर सर्विसेज के माध्यम से अंगदान के लिए सहमत हो गए।

जैसे ही अंगदान सर्जरी को लेकर बातें शुरू हुईं तो गैलेगोस के परिवार ने उनकी आंखों में आंसू देखे, जिन्हें सहज क्रियाएं बताकर खारिज कर दिया। सर्जरी की प्रक्रिया वाले दिन गैलेगोस की एक बहन ने उनकी आंखों में हलचल देखी। इसके बाद एक डॉक्टर ने गैलेगोस को पलकें झपकाने को कहा, जो उन्होंने झपकाईं, जिससे संकेत मिलता था कि वह अभी भी जीवित हैं इतना सबकुछ होने के बाद डोनेशन कोऑर्डिनेटर्स ने कथित तौर पर अस्पताल के कर्मचारियों पर आगे बढ़ने

का दबाव डाला और हलचल कम करने के लिए मॉर्फिन देने का सुझाव दिया। सौभाग्य से, डॉक्टरों ने मना कर दिया और सर्जरी रोक दी गई, इस फैसले ने गैलेगोस की जान बचाई और वह पूरी तरह ठीक हो गईं।

डैनेला गैलेगोस द न्यू यॉर्क टाइम्स को बताया, "मैं बहुत भाग्यशाली महसूस करती हूं लेकिन यह सोचकर भी अजीब लगता है कि चीजें कितनी जल्दी अलग तरह से समाप्त होने वाली थीं।" बाद में उन्होंने स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद इस घटना की जांच शुरू हुई। प्रेस्बिटेरियन अस्पताल ने कहा कि न्यू मैक्सिको डोनर सर्विसेज दान प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार थी, जबकि संगठन ने चिकित्सा निर्णयों में हस्तक्षेप करने से इनकार किया। गौरतलब है कि,अमेरिका में इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। अक्टूबर 2021 में केंटकी में थॉमस 'टीजे' हूवर II से जुड़ा एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जब दवा के ओवरडोज की वजह से हूवर को ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया था और उनका अंगदान किया जाना था, हालांकि इस ऑपरेशन से पहले एक कर्मचारी ने उन्हें छटपटाते और रोते हुए देखा था। जिसके बाद (केंटकी ऑर्गन डोनर एफिलिएट्स) पर प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का दबाव डाला लेकिन कंपनी ने मना कर दिया, जिसके बाद हूवर पूरी तरह से ठीक हो गए और अब अपनी बहन के साथ रहते हैं।

हमारा लक्ष्य हमास का पूरा सफाया और बंधकों की रिहाई है – नेतन्याहू

तेल अवीव – दक्षिण गाजा में मारे गए 29 और फिलिस्तीनी, गाजा में इजरायली सेना लगातार हमले कर रही है। इस दौरान गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि इजरायल जानबूझकर वितरण केंद्रों पर भोजन देने के लिए बुलाकर फिलिस्तीनियों की हत्या कर रहा है। दक्षिणी गाजा में बृहस्पतिवार को इजरायली सेना के हवाई हमलों और गोलीबारी में कम से कम 29 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। स्थानीय अस्पतालों के अनुसार, दक्षिणी शहर खान यूनिस में स्थित नासिर अस्पताल ने बताया कि मरने वालों में 12 लोग ऐसे थे जो एक अमेरिकी-इज़रायली समर्थित निजी ठेकेदार की सहायता वितरण साइट के पास सहायता लेने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरा टारगेट हमास का सफाया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनका उद्देश्य गाजा पट्टी पर कब्जा जमाना या उसे इजरायल में मिलाना नहीं है, बल्कि हमास को पूरी तरह नष्ट करना और बंधकों को सुरक्षित वापस लाना है। उन्होंने कहा कि इजरायल इस युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करना चाहता है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "हम गाजा को एक गैर-सैन्यीकृत क्षेत्र बनाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य स्थायी शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना है, न कि जमीन पर कब्जा करना।"

बताया जा रहा है कि इज़रायली सेना के इस हमले में कम से कम 50 लोग घायल हुए हैं। हालांकि गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने अभी तक हमले या गोलीबारी पर कोई टिप्पणी नहीं दी है। जबकि इज़रायली सेना ने आरोप लगाया है कि हामास नागरिक क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों को अंजाम देता है।

इज़रायल के सेना प्रमुख जनरल एयाल ज़मीर ने चेतावनी दी है कि यह अभियान बंधकों के लिए खतरा बन सकता है और पहले से ही थकी हुई इज़रायली सेना पर अतिरिक्त दबाव डालेगा। इज़रायली मीडिया इसे सेना और नेतन्याहू के बीच मतभेद के रूप में देख रही है। इसके अलावा बंधकों के परिवारों और सामान्य नागरिकों ने भी नेतन्याहू की इस योजना का विरोध किया है। बंधकों के परिवारों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से नेतन्याहू पर दबाव डालने की अपील की। ताकि युद्ध रोका जा सके और उनके प्रियजनों की जान बचाई जा सके। इज़रायली अधिकारियों ने एक फिलिस्तीनी कार्यकर्ता औदा अल हथलीन का शव उसके परिवार को लौटा दिया। हथलीन की कथित तौर पर एक चरमपंथी इज़रायली बस्तिवासी द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस फैसले के खिलाफ बेदुइन महिलाओं ने भूख हड़ताल शुरू की थी। हथलीन "नो अदर लैंड" नामक ऑस्कर विजेता डॉक्यूमेंट्री के सहयोगी थे। ह्यूमन राइट्स वॉच ने दो फिलिस्तीनी स्कूलों पर इज़रायली हमलों की जांच के बाद दुनिया भर की सरकारों से इज़रायल को हथियारों की आपूर्ति रोकने की मांग की है। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने कहा कि गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के खाद्य वितरण स्थल "मदद नहीं, बल्कि मौत बांटी जा रही है।" MSF ने बताया कि 850 से अधिक मौतें गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन साइट्स के पास हुई हैं।

न्यूज गैलरी

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड़ सशक्तिकरण एवं स्वाभिमान योजना के आवेदन आमंत्रित

नागपुर – कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड़ सशक्तिकरण एवं स्वाभिमान योजना के अंतर्गत, सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग के माध्यम से अनुसूचित जाति और नवबौद्ध समुदायों के गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले भूमिहीन परिवारों को 4 एकड़ सूखी ज़मीन या 2 एकड़ सिंचित कृषि भूमि 100 प्रतिशत अनुदान के आधार पर प्रदान की जाती है। समाज कल्याण के सहायक आयुक्त ने इस योजना के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। तदनुसार, मौजा-मालेगांव और मौजा-गोंडीखापा, तालुका काटोल, जिला नागपुर में कृषि भूमि खरीदी जा चुकी है और चूँकि कृषि भूमि पात्र हितग्राहियों को वितरित की जानी है, इसलिए काटोल तालुका में पात्र हितग्राहियों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। योजना की शर्तें हैं कि आवेदक अनुसूचित जाति/नवबौद्ध वर्ग से होना चाहिए, आवेदक नागपुर जिले का निवासी होना चाहिए, आवेदक गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए (गरीबी रेखा से नीचे की सूची में नाम दर्ज होना चाहिए), आवेदक भूमिहीन कृषि मजदूर होना चाहिए, आवेदक की आयु सीमा 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए, गरीबी रेखा से नीचे की विधवाओं और परित्यक्ता व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है, और अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अत्याचार के पीड़ितों को प्राथमिकता दी जाती है। सुकेशिनी तेलगोटे, सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, नागपुर, एक सार्वजनिक अपील कर रही हैं कि नागपुर जिले में रहने वाले व्यक्तियों को उक्त योजना का लाभ लेने के लिए सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, श्रद्धानंद पेठ, नागपुर से आवेदन पत्र प्राप्त करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए, सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, नागपुर से संपर्क करें।

नए वाहन पंजीकरण के लिए पसंदीदा पंजीकरण संख्या प्राप्त करने की अपील

नागपुर – उप-क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय नागपुर (पूर्व) में चार पहिया वाहनों के लिए पंजीकरण संख्या एमएच-49-सीएल की श्रृंखला समाप्त होने के कारण, चार पहिया वाहनों के लिए एक नई श्रृंखला एमएच-49-सीएस 8 अगस्त को शुरू की जा रही है। जो वाहन मालिक अपने वाहनों के लिए इस श्रृंखला से एक आकर्षक या पसंदीदा पंजीकरण संख्या आरक्षित करना चाहते हैं, उन्हें निर्धारित प्रारूप में आवेदन के साथ निवास प्रमाण, फोटो पहचान पत्र, पैन कार्ड और पसंदीदा पंजीकरण संख्या के साथ "उप-क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, नागपुर (पूर्व)" के नाम से निकाले गए शुल्क के साथ 8 अगस्त को सुबह 11 बजे से दोपहर 2.30 बजे के बीच नए वाहन पंजीकरण विभाग कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जमा करना चाहिए, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने अपील की है।

संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र नई दिल्ली में पहली वार्षिक ट्राइडेंट व्याख्यान श्रृंखला का शुभारंभ करेगा

नई दिल्ली – संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र (सीईएनजेओडब्लयूएस) अपने स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 5 अगस्त, 2025 को मानेकशॉ केंद्र, दिल्ली कैंट में पहली वार्षिक ट्राइडेंट व्याख्यान श्रृंखला (एटीएलएस) का शुभारंभ करेगा। इस अवसर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान 'भविष्य के युद्धक्षेत्र पर प्रभुत्व' विषय पर उद्घाटन व्याख्यान देंगे। यह व्याख्यानमाला युद्ध के उभरते चरित्र, तकनीकी परिवर्तनों और तेजी से बदलते प्रतिस्पर्धी रणनीतिक वातावरण में निर्बाध संयुक्त बल एकीकरण की अनिवार्यता पर विचार-विमर्श के लिए माहौल तैयार करेगा। इस कार्यक्रम का एक प्रमुख आकर्षण 'मानव-मानव रहित टीमिंग' पर 'जनरल बिपिन रावत पेपर' का विमोचन होगा। इसमें भारत के पहले सीडीएस को श्रद्धांजलि दी जाएगी, जिनकी दूरदर्शिता, संयुक्त प्रयास, सैन्य आधुनिकीकरण और एकीकृत सिद्धांतों पर चर्चा को आकार देती रही है। कार्यक्रम में वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व द्वारा विभिन्न विषयों पर संबोधन भी दिए जाएंगे। इनमें एकीकृत रक्षा स्टाफ के उप प्रमुख द्वारा 'भविष्य के युद्ध में भारतीय विरासत की रणनीति को आत्मसात करना' और एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख द्वारा 'तीनों सेनाओं में सुधारों की तत्काल आवश्यकता' शामिल हैं।

दिव्यांग भाई-बहनों की प्रगति से ही 'विकसित भारत' का सपना – राज्यपाल राधाकृष्णन

मुंबई – भारत 2047 तक विकसित देश बनना चाहता है। राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन ने मुंबई विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित राष्ट्रीय तैराकी चैम्पियनशिप 2025 के पुरस्कार वितरण समारोह में आशा व्यक्त की कि दिव्यांगों की प्रगति से ही विकसित भारत का सपना पूरा होगा।

कार्यक्रम में दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे, स्पेशल ओलंपिक्स इंडिया की अध्यक्ष डॉ. मल्लिका नड्डा, स्पेशल ओलंपिक्स इंडिया महाराष्ट्र शाखा की अध्यक्ष डॉ. मेधा सोमैया, महाराष्ट्र स्पेशल ओलंपिक्स इंडिया के महासचिव डॉ. भगवान तलवारे, एथलीट करण नाइक, मुर्तुजा वर्दावाला और अन्य उपस्थित थे। राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन ने कहा कि महाराष्ट्र के हर जिले में मानसिक रूप से दिव्यांगों के पुनर्वास और सर्वांगीण विकास का केंद्र खेल होना चाहिए। मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में 40 से अधिक स्पर्धाएँ आयोजित की गई हैं। यह उनकी एकाग्रता, समर्पण और सेवा का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में दिव्यांगों के लिए कई सुधार किए हैं। 2016 में लागू "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम" के तहत दिव्यांगता की श्रेणियों में वृद्धि की गई है। साथ ही, केंद्रीय सेवाओं में दिव्यांगों के लिए आरक्षण तीन से बढ़ाकर चार प्रतिशत और शिक्षा में इसे बढ़ाकर पाँच प्रतिशत कर दिया गया है, ऐसा राज्यपाल श्री राधाकृष्णन ने कहा।

राज्य ने एक अलग 'दिव्यांग कल्याण विभाग' की स्थापना की है। मैं राज्य सरकार को इस विभाग के अंतर्गत बौद्धिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए कई महत्वपूर्ण पहलों को लागू करने के लिए बधाई देता हूँ। बौद्धिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की समस्याएँ अन्य विकलांग व्यक्तियों की तुलना में भिन्न और अधिक संवेदनशील होती हैं। बौद्धिक रूप से अक्षम व्यक्ति समाज से स्वीकृति, प्रोत्साहन और अवसरों की अपेक्षा करते हैं। संस्थाओं, विद्यालयों, स्थानीय स्वशासन निकायों, सभी को मिलकर विकलांगों के लिए एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी चाहिए जो केवल उपचार या शिक्षा तक सीमित न रहे, बल्कि उनके संपूर्ण जीवन को सामंजस्यपूर्ण बनाए। सरकार विकलांगों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयासरत है, लेकिन एक समाज के रूप में हमारी भूमिका व्यापक होनी चाहिए। राज्यपाल श्री राधाकृष्णन ने भी इस अवसर पर ज़ोर दिया। विशेष ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन लगातार बेहतर हो रहा है। राज्यपाल ने इस बात पर भी गर्व व्यक्त किया कि हमारे खिलाड़ियों ने 2023 में बर्लिन में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेलों में 200 से अधिक पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया है।

देश में पिछले 32 वर्षों से विशेष ओलंपिक आयोजित हो रहा है। मुंबई में बौद्धिक रूप से दिव्यांगों के लिए राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता में राज्य के 27 जिलों के साथ-साथ अन्य राज्यों के प्रतियोगियों ने भाग लिया था। दिव्यांगों के लिए खेलों को बढ़ावा देने और सुविधाएँ प्रदान करने के लिए, केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में दिव्यांगों के लिए विशेष खेल मैदान का निर्माण किया जाएगा, ऐसा जानकारी दिव्यांग कल्याण और दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे ने दी। राज्य के दिव्यांगों के लिए स्कूलों में ओपन जिम की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें उनके लिए आवश्यक उपकरण शामिल होंगे, ऐसा जानकारी मंत्री श्री सावे ने दी।

कार्यक्रम की शुरुआत मेधा सोमैया ने की। उन्होंने प्रतियोगिता के आयोजन की भूमिका के बारे में बताया। स्पेशल ओलंपिक इंडिया की अध्यक्ष मल्लिका नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार ने दिव्यांगों के लिए खेलों हेतु अनुदान राशि 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी है। तैराकी प्रतियोगिता में विभिन्न स्पर्धाओं में कांस्य, रजत और स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पदक देकर सम्मानित किया गया। धावक करण नाइक ने कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों से आए प्रतियोगी और प्रशिक्षक उपस्थित थे।

एक स्क्रीन के संबंध में संयुक्त समिति गठित करें – आशीष शेलार

मुंबई – सांस्कृतिक मामलों के मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार ने एकल स्क्रीन सिनेमाघरों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए संबंधित विभागों की एक संयुक्त समिति बनाने का निर्देश दिया है ताकि मराठी फिल्मों के लिए अधिक से अधिक सिनेमाघर उपलब्ध हो सकें। महाराष्ट्र में एकल स्क्रीन वाले सिनेमाघरों की समस्या के समाधान, अनुदान और सहायता की मांग को लेकर विभिन्न संगठनों और सिनेमाघर मालिकों, संचालक संघों, कलाकारों और फिल्म निर्माताओं ने सांस्कृतिक कार्य मंत्री एडवोकेट शेलार को एक ज्ञापन सौंपा था। इस संबंध में सांस्कृतिक कार्य विभाग, गोरेगांव फिल्म सिटी और संबंधित अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई। इस बैठक में सिनेमाघर मालिकों के संघ के पदाधिकारी उपस्थित थे। सांस्कृतिक कार्य मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार ने कहा कि नगरीय विकास, गृह, राजस्व, वित्त और सांस्कृतिक कार्य विभागों तथा इस क्षेत्र के विशेषज्ञों की एक संयुक्त समिति बनाकर इस पर विस्तृत अध्ययन किया जाए और दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। साथ ही, यदि सभी 300 खुले और बंद सिनेमाघरों में मराठी फिल्में दिखाई जानी हैं, तो इसके लिए समिति को कुछ प्रोत्साहन योजना पर भी विचार करना चाहिए, ऐसा निर्देश मंत्री श्री शेलार ने दिया। इस बीच, मुंबई के गोरेगांव में प्रस्तावित थिएटर के संबंध में भी एक बैठक हुई। अभिनेता सुनील बर्वे और गोरेगांव के नागरिक इस थिएटर के लिए आग्रह कर रहे हैं और इसके लिए एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। मंत्री श्री शेलार ने विधायक विद्या ठाकुर, नगर निगम के अधिकारियों और संबंधित कलाकारों की उपस्थिति में एक बैठक में इसकी समीक्षा की। प्रस्तावित भवन के संबंध में उपलब्ध स्थान और कलाकारों के विचारों पर विचार किया जाए और अगले पंद्रह दिनों के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। मंत्री श्री शेलार ने निर्देश दिया कि जल्द से जल्द काम शुरू करने के लिए कार्रवाई की जाए। बैठक में लावणी कलाकारों के मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

इतिहास से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं – शेलार

मुंबई – सांस्कृतिक मामलों के मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार ने दृढ़तापूर्वक कहा, "इतिहास से छेड़छाड़ किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जाएगी।" फिल्म 'खालिद का शिवाजी' को लेकर मिली शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए, राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से फिल्म की तुरंत दोबारा जाँच करने का अनुरोध किया है। शिव समर्थ प्रतिष्ठान के आयोजक नीलेश भिसे ने शेलार से मुलाकात की और फिल्म के खिलाफ एक शिकायत और बयान प्रस्तुत किया। आरोप लगाया गया है कि फिल्म में ऐसे दृश्य और संवाद हैं जो इतिहास को विकृत करते हैं और जनभावनाओं को ठेस पहुँचाते हैं। इस पृष्ठभूमि पर बोलते हुए, शेलार ने कहा कि फिल्म सेंसरशिप बोर्ड केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। प्रशासन को इस फिल्म की पुनः जाँच के संबंध में केंद्र सरकार से तुरंत पत्राचार करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो वे संबंधित केंद्रीय मंत्रियों और अधिकारियों से भी चर्चा करेंगे। राज्य सरकार को इस फिल्म के खिलाफ बड़ी संख्या में शिकायतें और ज्ञापन मिले हैं, जिनमें आरोप लगाया गया है कि इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में गलत और विकृत जानकारी दी गई है। शेलार ने यह भी स्पष्ट किया कि इतिहास के विद्वानों और शिव प्रेमियों ने फिल्म के कई संवादों पर कड़ी आपत्ति जताई है। इस पृष्ठभूमि में, सांस्कृतिक मामलों के विभाग की सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण विभाग के सचिव को एक पत्र भेजकर अनुरोध किया है कि फिल्म की पुनः जांच की जाए, दिए गए प्रमाण पत्र पर पुनर्विचार किया जाए और पुनः जांच होने तक फिल्म का प्रदर्शन रोक दिया जाए। शेलार ने आगे कहा कि इस फिल्म को केंद्रीय सेंसर बोर्ड का प्रमाणपत्र कैसे मिला? क्या स्क्रीनिंग कमेटी ने फिल्म का सही अध्ययन किया था? इस संबंध में जाँच होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस फिल्म का चयन कान फिल्म महोत्सव के लिए कैसे हुआ और क्या इसमें कोई गड़बड़ी हुई है, इसकी भी जाँच की जाएगी।

अपूर्ण नहीं, बल्कि स्व-निर्मित, मन में है विश्वास, हम होंगे कायम!

उनकी दुनिया अलग है... शब्दों से परे, बस उनकी आँखों में प्रतीकात्मक संकेत और भाव हैं। हम शायद इस भाषा को आसानी से न समझ पाएं, लेकिन उनकी आंखों की चमक देखिए... उसमें हमें भविष्य के प्रति अटूट विश्वास दिखाई देता है। मानो वे बिना बोले ही पूरी दुनिया को बता रहे हों, "हम अपूर्ण नहीं हैं, हम स्वयं निर्मित हैं! तुम बस अपने विश्वास का हाथ हमारी पीठ पर रखो और कहो कि लड़ो, फिर देखो हम कैसे इस दुनिया को तुम्हारे हाथों में सौंप देते हैं!"

यह मौन, फिर भी बेहद प्रभावशाली संवाद मिराज के स्वर्गीय आर. वी. भिड़े मूक-बधिर विद्यालय की चारदीवारी के भीतर गूंज रहा था। यह एक ऐतिहासिक बदलाव का अवसर था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और रोबोटिक्स की दुनिया के दरवाज़े उन बच्चों के लिए खुल रहे थे जिनके बारे में हम सोचते थे कि वे समाज की प्रतिस्पर्धा में पीछे छूट जाएंगे।

इस स्वप्न-जैसे कार्य को सांगली के जिला कलेक्टर अशोक काकड़े ने साकार किया। उन्होंने न केवल "हमारा सांगली - सक्षम दिव्यांग, हमारा गौरव" के आदर्श वाक्य को अपनाया, बल्कि उसे अमल में भी लाया। पुणे के 'वर्शिप अर्थ फाउंडेशन' द्वारा उनकी इस अवधारणा को मिली प्रतिक्रिया इन बच्चों के भाग्य में एक सुनहरा सवेरा लेकर आई। पिछले 15 दिनों से, रोज़ाना तीन घंटे, इस स्कूल की कक्षाएँ जीवंत हो उठी हैं। यहाँ के 73 लड़के-लड़कियों के हाथों में पंख उग आए हैं जो भविष्य को आकार देंगे। जब उन्होंने 3-डी प्रिंटर का उपयोग करके गणपति बप्पा की मूर्ति बनाई, तो यह महज एक प्रयोग नहीं था, बल्कि उनकी छिपी रचनात्मकता का पहला उदाहरण था।

जब उन्होंने सेंसर का उपयोग करके आग लगने या बिजली गुल होने की स्थिति में बजने वाला अलार्म बनाया, तो वे न केवल विज्ञान सीख रहे थे, बल्कि यह भी अनुभव कर रहे थे कि प्रौद्योगिकी किस प्रकार हमारी मित्र और रक्षक हो सकती है।

जब उन्होंने चैट-जीपीटी में अपने विचारों को चित्रों में टाइप किया, तो उन्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं रही। तकनीक ने उन्हें एक नई 'भाषा', एक नई 'आवाज़' दी!

जिन बच्चों को अब तक सिर्फ़ सहानुभूति ही मिली थी, इस कार्यशाला ने उन्हें आत्मविश्वास और समान अवसर की शक्ति दी। उनके लिए STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित) जैसे जटिल प्रतीत होने वाले क्षेत्रों के द्वार खुल गए।

यह सिर्फ़ एक कार्यशाला नहीं थी; यह एक बड़े बदलाव की नींव थी। जो सुन या बोल नहीं सकते, उनके लिए यह खुद को अभिव्यक्त करने, सीखने और इस डिजिटल दुनिया में गर्व से आगे बढ़ने का एक नया रास्ता है। इस ज्ञान और आत्मविश्वास से लैस ये बच्चे कल न सिर्फ़ आत्मनिर्भर बनेंगे, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनेंगे।

क्योंकि वे अपूर्ण नहीं हैं, वे स्व-निर्मित हैं। और उनकी यात्रा अब सचमुच शुरू हो गई है!

– **संप्रदाय बीडकर**
जिला सूचना अधिकारी,
सांगली

पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल अवसंरचना को बढ़ावा देने 777 किलोमीटर लंबी 12 नई परियोजनाओं को मंजूरी, लागत 69,000 करोड़ से अधिक होगी

नई दिल्ली – वित्त वर्ष 2022-23 से प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 1790 किलोमीटर के 17 रेलवे सर्वेक्षण स्वीकृत। पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल नेटवर्क की लाइन क्षमता को बढ़ाने के लिए 777 किलोमीटर लंबी 12 रेलवे परियोजनाओं (08 नई लाइनें, 04 दोहरीकरण) स्वीकृत किया गया है। पूर्णतः/आंशिक रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) की इन परियोजनाओं की लागत 69,342 करोड़ है। मार्च 2025 तक इनमें से 278 किलोमीटर की लाइन चालू हो चुकी है और 41,676 करोड़ का व्यय हो चुका है। ।

पिछले तीन वर्षों अर्थात वित्त वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 और चालू वित्त वर्ष के दौरान, पीएम गति शक्ति एनएमपी के अंतर्गत उत्तर पूर्व क्षेत्र में पूर्णतः/आंशिक रूप से आने वाले कुल 1790 किलोमीटर लंबाई के 17 सर्वेक्षण (13 नई लाइन और 4 दोहरीकरण) स्वीकृत किए गए हैं। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार होने के बाद, परियोजना की स्वीकृति के लिए राज्य सरकार सहित विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श और नीति आयोग, वित्त मंत्रालय से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। चूँकि परियोजनाओं की स्वीकृति एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है। इसलिए सटीक समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

इसी प्रकार पूर्वोत्तर रेलवे में स्थित रेल नेटवर्क की लाइन क्षमता में वृद्धि और संवर्द्धन हेतु, 01.04.2025 तक पूर्वोत्तर रेलवे पर 20,466 करोड़ की लागत से कुल 1,253 किलोमीटर लंबाई की कुल 17 रेलवे अवसंरचना परियोजनाएँ (08 नई लाइन, 01 आमान परिवर्तन और 08 दोहरीकरण) स्वीकृत की गई हैं। इनमें से 354 किलोमीटर की लाइन चालू हो चुकी है और मार्च 2025 तक 10,486 करोड़ का व्यय हो चुका है। सारांश इस प्रकार है:

पिछले तीन वर्षों (2022-2023, 2023-2024, 2024-2025) और वर्त्तमान वित्त वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर रेलवे पर कुल 1878 किलोमीटर लंबाई के 46 सर्वेक्षण (5 नई लाइन, 2 आमान परिवर्तन और 39 दोहरीकरण) स्वीकृत किए गए हैं। रेलवे परियोजना/परियोजनाओं का पूरा होना विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जैसे राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वन मंजूरी, अतिक्रमणकारी उपयोगिताओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से वैधानिक मंजूरी, क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक स्थितियाँ, परियोजना/परियोजनाओं के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति, किसी विशेष परियोजना स्थल के लिए वर्ष में कार्य महीनों की संख्या आदि। ये सभी कारक परियोजना/परियोजनाओं के पूरा होने के समय और लागत को प्रभावित करते हैं। यह जानकारी केंद्रीय रेल, सूचना और प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

रीवा-हडपसर-रीवा के बीच नई एक्सप्रेस ट्रेन से बढ़ेगा संपर्क

मध्य रेल द्वारा रीवा (मध्यप्रदेश) और हडपसर (पुणे, महाराष्ट्र) के बीच एक नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई है, जिससे अंतरराज्यीय संपर्क और यात्रियों की सुविधा में वृद्धि होगी। यह नई ट्रेन सेवा उत्तर मध्यप्रदेश और पश्चिम महाराष्ट्र के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करेगी, जिससे नौकरीपेशा लोग, विद्यार्थी, पर्यटक और आम यात्री जो कार्य, शिक्षा या भ्रमण हेतु यात्रा करते हैं, उन्हें लाभ मिलेगा। ट्रेन क्रमांक 20152 की नियमित सेवा से रीवा से आरंभ होगी, और ट्रेन क्रमांक 20151 की सेवा हडपसर से शुरू होगी। ट्रेन विवरण: ट्रेन क्रमांक 20152 रीवा–हडपसर एक्सप्रेस (साप्ताहिक) हर बुधवार को प्रातः 06:45 बजे रीवा से प्रस्थान करेगी और अगले दिन प्रातः 09:45 बजे हडपसर पहुंचेगी। यह ट्रेन उसी दिन सायं 18:20 बजे नागपुर पहुंचेगी। ट्रेन क्रमांक 20151

हडपसर–रीवा एक्सप्रेस (साप्ताहिक) हर गुरुवार को अपराह्न 15:15 बजे हडपसर से प्रस्थान करेगी और अगले दिन सायं 17:30 बजे रीवा पहुंचेगी। यह ट्रेन अगले दिन प्रातः 05:25 बजे नागपुर पहुंचेगी। प्रमुख ठहराव स्टेशन: सतना, मैहर, कटनी, जबलपुर, नैनीपुर, बालाघाट, गोंदिया, नागपुर, वर्धा, बडनेरा, अकोला, भुसावल, जलगांव, मनमाड, कोपरगांव, अहमदनगर, दौंड छार्ड लाइन। कोच संरचना: 2 एसएलआरडी, 4 सामान्य, 6 स्लीपर, 3 तृतीय एसी, 3 इकोनॉमी एसी, 2 द्वितीय एसी कोच। इन नई ट्रेनों की शुरुआत के साथ मध्य रेल रेल संपर्क को सुदृढ़ करने तथा यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक और कुशल यात्रा सुविधाएं उपलब्ध कराने के अपने संकल्प को दोहराता है। प्रेस विज्ञप्ति मध्य रेल, नागपुर मंडल के जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी की गई है।